

Eighteenth Series, Vol. I No. 4

Thursday, June 27, 2024

Ashadha 6, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

First Session

(Eighteenth Lok Sabha)



(Vol. I contains Nos. 1 to 7)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Mamta Kemwal
Joint Secretary

Bishan Kumar
Director

Narad Prasad Kimothi
Sunita Thapliyal
Joint Director

Maneesha Bhushan
Pankaj Kumar Singh
Deputy Director

© 2024 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Eighteenth Series, Vol. I, First Session, 2024/1946 (Saka)
No. 4, Thursday, June 27, 2024/ Ashadha 6, 1946 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
OBSERVATION BY THE SPEAKER	
Usage of Lok Sabha Chamber as Venue of the President's Address Relaxing Rule 384	4
INTRODUCTION OF THE LEADER OF OPPOSITION	5
MEMBER SWORN	6
PRESIDENT'S ADDRESS	7-43
ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER	
Notices of Amendments to Motion of Thanks on President's Address	44
ASSENT TO BILLS	45-46

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS*

Shri Kodikunnil Suresh

Shri T. R. Baalu

Shri Radha Mohan Singh

Dr. Faggan Singh Kulaste

Shri Sudip Bandyopadhyay

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

* Nominated on 20.06.2024.

The following order was issued by the President of India on 20.06.2024.

I hereby appoint Shri Suresh Kodikunnil, Shri Thalikkottai Rajuthevar Baalu, Shri Radha Mohan Singh, Shri Faggan Singh Kulaste and Shri Sudip Bandyopadhyay to be the persons before any of whom Members of the House of the People may make and subscribe the oath or affirmation in accordance with provision of article 99 of the Constitution of India.

**Droupadi Murmu,
PRESIDENT OF INDIA**

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, June 27, 2024/ Ashadha 6, 1946 (Saka)

The Lok Sabha met at Thirty-Eight Minutes past Twelve of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

OBSERVATION BY THE SPEAKER**Usage of Lok Sabha Chamber as Venue of the President's Address Relaxing
Rule 384**

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति एक साथ समवेत दोनों सभाओं को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में दोनों सभाओं के सभी सदस्य बिना किसी कठिनाई के उपस्थित हो सकें, इसलिए मैं सभा की ओर से लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 384 में छूट देते हुए इस कक्ष का उपयोग राष्ट्रपति के अभिभाषण के स्थान के रूप में करने के प्रस्ताव पर सहमत हूँ। मैं आशा करता हूँ कि सभा इससे सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

12.39 hrs

INTRODUCTION OF THE LEADER OF OPPOSITION

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि मैंने संसद में विपक्ष के नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 की धारा 2 के निबंधनों के अनुसार लोक सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी को 9 जून, 2024 से लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: महासचिव जी ।

... (व्यवधान)

12.39½ hrs

MEMBER SWORN – Contd.

SECRETARY GENERAL: Kerala - Shri Shashi Tharoor. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: शपथ ग्रहण की एक मान्यता रहती है, आप सीनियर व्यक्ति हैं, कुछ न बोलें ।

... (व्यवधान)

KERALA

Shri Shashi Tharoor (Thiruvananthapuram) — Oath - English

माननीय अध्यक्ष : संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह संविधान की शपथ है ।

... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: किस पर आपत्ति है, किस पर नहीं, आप सलाह मत दिया करें । आप बैठिए ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: महासचिव ।

12.41 hrs

PRESIDENT'S ADDRESS*

SECRETARY-GENERAL: Sir, I beg to lay on the Table a copy of the President's Address (Hindi and English versions) to both the Houses of Parliament assembled together on the 27th June, 2024.

**माननीय सदस्यगण, मैं 18वीं लोक सभा के सभी नव निर्वाचित सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। आप सभी यहां देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर आए हैं। देशसेवा और जनसेवा का ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है, आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। मैं श्री ओम बिरला जी को लोक सभा के अध्यक्ष की गौरवपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं देती हूं। उनके पास सार्वजनिक जीवन का बहुत व्यापक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने कौशल से नई ऊंचाई देने में सफल होंगे।

माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि-कोटि देशवासियों की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूं। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू-कश्मीर से भी सामने आई है। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन, इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू-कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे। लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने, देश और दुनिया में ऐसी हर ताकत

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 02/18/24.

** Her Excellency Shrimati Dropadi Murmu, President of India, delivered the Address in Lok Sabha Chamber, Parliament House of India (New building of Parliament) in Hindi and the English Text of the Address was read by His Excellency, Shri Jagdeep Dhankhar, Vice President of India.

को करारा जवाब दिया है। पहली बार, इस लोक सभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोक सभा चुनाव से जुड़े हर कर्मी की सराहना करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ।

माननीय सदस्यगण, 2024 के लोक सभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। छः दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसे समय में जब भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर हैं, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नीयत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत को विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करे।

माननीय सदस्यगण, 18वीं लोक सभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोक सभा है। ये लोक सभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोक सभा, देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्ष की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोक सभा में जन कल्याण के फैसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और futuristic vision का एक प्रभावी दस्तावेज़ होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए Reforms की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार का मत है कि दुनियाभर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो। यही कंपटीटिव को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे।

माननीय सदस्यगण, Reform, Perform और Transform के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर पांचवें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत ने औसतन 8 प्रतिशत की रफ्तार से विकास किया है। और ये ग्रोथ सामान्य समय में नहीं हुई है। बीते वर्षों में हमने 100 साल की सबसे बड़ी आपदा देखी है। वैश्विक महामारी के कालखंड और विश्व के अलग-अलग कोनों में चल रहे संघर्षों के बावजूद भारत ने ये विकास दर हासिल की है। ये बीते 10 साल के रिफॉर्म और राष्ट्रहित में लिए गए बड़े फैसलों के कारण संभव हुआ है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। अब मेरी सरकार भारत को विश्व की तीसरे नंबर की इकॉनॉमी बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने का काम करेगी।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों - Manufacturing, Services और Agriculture को बराबर महत्व दे रही है। PLI schemes और Ease of Doing Business से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पारंपरिक सेक्टरों के साथ-साथ sunrise सेक्टरों को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हों या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हों, चाहे ग्रीन हाईड्रोजन हो या बैटरीज हों, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फाइटर जेट्स हों, भारत इन सब सेक्टरों में अपना विस्तार कर रहा है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए भी मेरी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करने में जुटी है। आज IT से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है। और इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, पिछले 10 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया गया है। गांवों में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है। सरकार, किसान उत्पाद

संघ-FPO और PACS (पैक्स) जैसे सहकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़ी होती है। इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू किया है। किसान अपने छोटे खर्चें पूरे कर सकें, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी जा चुकी है। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही किसानों को 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है।

माननीय सदस्यगण, आज का भारत, अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हों और ज्यादा से ज्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई गई हैं, निर्णय लिए गए हैं। जैसे सरकार दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के किसानों को हर संभव मदद दे रही है। ग्लोबल मार्केट में किस तरह के फूड प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, उसके आधार पर नई रणनीति बनाई जा रही है। आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने की भरपूर क्षमता है। इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाय चेन को सशक्त कर रही है। ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी और बढ़ेगी।

माननीय सदस्यगण, आज का भारत, दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए जाना जाता है। विश्व-बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं। हमारे मोटे अनाज - श्री अन्न - की पहुंच सुपरफूड के तौर पर दुनिया के कोने-कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। भारत की पहल पर, पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स डे मनाया है। आपने देखा है, हाल ही में पूरी दुनिया ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है। भारत की इस महान परंपरा की प्रतिष्ठा विश्व में

लगातार बढ़ रही है। योग और आयुष को बढ़ावा देकर भारत एक स्वस्थ विश्व के निर्माण में मदद कर रहा है। मेरी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता भी कई गुना बढ़ाई है। हम जलवायु से जुड़े लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले प्राप्त करके दिखा रहे हैं। नेट जीरो के लिए आज भारत के प्रयास कई दूसरे देशों को प्रेरित कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल पर आज रिकॉर्ड संख्या में दुनिया के देश हमारे साथ जुड़े हैं।

माननीय सदस्यगण, आने वाला समय Green Era यानि हरित युग का है। मेरी सरकार इसके लिए भी हर ज़रूरी कदम उठा रही है। हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे Green Jobs भी बढ़े हैं। Green एनर्जी हो या फिर Green मोबिलिटी, हर मोर्चे पर हम बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रहे हैं। मेरी सरकार अपने शहरों को दुनिया के बेहतरीन लिविंग स्पेस बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदूषण से मुक्त, साफ-सुथरे और सुविधा युक्त शहरों में रहना भारत के नागरिकों का हक है। विशेष रूप से छोटे शहरों और कस्बों में बीते 10 वर्षों में अभूतपूर्व निवेश किया गया है। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। अप्रैल 2014 में भारत में सिर्फ 209 एयरलाइन रूट्स थे। अप्रैल 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 605 हो गई है। हवाई यात्रा में हो रहे इस विस्तार का सीधा लाभ टीयर-2, टीयर-3 शहरों को हो रहा है। 10 वर्षों में देश के 21 शहरों तक मेट्रो सुविधाएं पहुंची हैं। वंदे मेट्रो जैसी कई योजनाओं पर काम चल रहा है। भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुनिया में बेहतरीन हो, इस लक्ष्य के साथ मेरी सरकार काम कर रही है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार उन आधुनिक मानदंडों पर काम कर रही है, जिससे भारत विकसित देशों के सामने बराबरी से खड़ा हो सके। इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की नई तस्वीर के रूप में उभरा है। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांवों में 3 लाख 80 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई हैं। आज भारत में नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है। नेशनल हाईवे बनाने की गति में भी दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है। अहमदाबाद-मुंबई के बीच हाई-स्पीड रेल इकोसिस्टम का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में Bullet train corridors के लिए feasibility

studies शुरू करने का फैसला किया है। पहली बार देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास पर इतने व्यापक रूप से काम शुरू हुआ है। इसका बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आबंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार इस क्षेत्र को Act East Policy के तहत strategic gateway बनाने के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। असम में 27 हजार करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है। यानि नॉर्थ ईस्ट, मेड इन इंडिया चिप्स का भी सेंटर होने वाला है। मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थाई शांति के लिए निरंतर काम कर रही है। पिछले दस वर्षों में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया है, अनेक अहम समझौते हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्रों में तेज विकास करके चरणबद्ध तरीके से AFSPA हटाने का काम भी जारी है। देश के हर क्षेत्र में विकास के ये नए आयाम भारत के भविष्य का उद्घोष कर रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, Women-led-development के लिए समर्पित मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है। देश की नारीशक्ति लंबे समय तक लोक सभा और विधान सभा में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी। आज उनके पास नारी शक्ति वंदन अधिनियम की ताकत है। सरकार की योजनाओं की वजह से पिछले एक दशक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। आप जानते हैं कि बीते 10 वर्ष में बने 4 करोड़ पीएम आवास में से ज्यादातर महिलाओं के नाम ही आबंटित हुए हैं। अब तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने को स्वीकृति दे दी है। इनमें से भी अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर ही आबंटित होंगे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी हैं। मेरी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का एक व्यापक अभियान चलाया है। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद भी बढ़ाई जा रही है। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं का कौशल बढ़े, कमाई के साधन बढ़ें और उनका सम्मान बढ़े। नमो ड्रोन दीदी योजना इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बन रही है। इस योजना के तहत हजारों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं, ड्रोन पायलट बनने की

ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरी सरकार ने हाल में ही कृषि सखी कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके तहत अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 30 हजार महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। कृषि सखियों को आधुनिक खेती की तकनीक में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे कृषि को और आधुनिक बनाने में किसानों की मदद कर सकें।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का ये भी प्रयास है कि महिलाएं अधिक से अधिक बचत कर सकें। बैंक खातों में जमा राशि पर बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना की लोकप्रियता से हम परिचित हैं। मुफ्त राशन और सस्ते गैस सिलेंडर की योजना से महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। अब मेरी सरकार बिजली का बिल जीरो करने और बिजली बेचकर कमाई करने की योजना भी लाई है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसके लिए मेरी सरकार प्रति परिवार 78 हजार रुपए तक की मदद कर रही है। इतने कम समय में एक करोड़ से ज्यादा परिवार इस योजना में रजिस्टर करा चुके हैं। जिन घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं अब वहां बिजली का बिल जीरो हो गया है।

माननीय सदस्यगण, विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारीशक्ति और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार की योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं चार स्तंभों को दी जा रही है। हमारी कोशिश, इन तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की है, और यही सैचुरेशन की अप्रोच है। जब सरकार इस इच्छाशक्ति के साथ काम करे कि सरकारी योजना से एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, तो इसका लाभ सभी को होता है। सरकार की योजनाओं एवं सैचुरेशन अप्रोच के कारण ही 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के परिवार हैं। 10 वर्षों में लास्ट माइल डिलिवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। विशेषकर आदिवासी समाज में ये बदलाव और भी स्पष्ट नज़र आ रहा है। 24 हजार करोड़ रुपए से अधिक की पीएम-जनमन जैसी योजना आज अति पिछड़े जनजातीय समूहों के उत्थान का माध्यम बन रही है। सरकार, पीएम सूरज पोर्टल के माध्यम से वंचित वर्गों तक आजीविका के अवसरों को पहुंचाने के लिए सुलभ ऋण भी उपलब्ध करा रही है। मेरी

सरकार, दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए, किफायती और स्वदेशी सहायक उपकरण विकसित कर रही है। देश भर में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों का भी विस्तार किया जा रहा है। वंचितों की सेवा का ये संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है।

माननीय सदस्यगण, देश की श्रमशक्ति के सम्मान के लिए श्रमिक बंधुओं का कल्याण और सशक्तिकरण मेरी सरकार की प्राथमिकता है। मेरी सरकार श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत कर रही है। डिजिटल इंडिया तथा डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग करके दुर्घटना और जीवन बीमा के कवरेज को बढ़ाने का काम हो रहा है। पीएम स्वनिधि का विस्तार किया जाएगा और ग्रामीण और सेमी अर्बन क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी वाले भाई-बहनों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा।

माननीय सदस्यगण, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति समाज के निचले तबकों की प्रगति पर निर्भर करती है। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है। मेरी सरकार ने पहली बार गरीब को ये अहसास करवाया कि सरकार उसकी सेवा में है। कोरोना के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं, ताकि उनके कदम वापस पीछे न जाएं। स्वच्छ भारत अभियान ने भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तक को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। पहली बार देश में करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए। ये प्रयास हमें आश्चस्त करते हैं कि देश आज महात्मा गांधी के आदर्शों का सच्चे अर्थों में अनुसरण कर रहा है। मेरी सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवा रही है। देश में 25 हजार जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है। अब इस क्षेत्र में सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है। अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा।

माननीय सदस्यगण, अक्सर विरोधपरक मानसिकता और संकीर्ण स्वार्थ के कारण लोकतंत्र की मूल भावना का बहुत अहित हुआ है। इसका प्रभाव संसदीय प्रणाली पर भी पड़ता है और देश की विकास यात्रा पर भी पड़ता है। देश में कई दशकों तक अस्थिर सरकारों के दौर में कई सरकारें चाहेते हुए भी न Reform कर पाईं और न ही आवश्यक निर्णय ले पाईं। भारत की जनता ने निर्णायक बनकर इस स्थिति को बदला है। बीते 10 वर्ष में ऐसे अनेक Reforms हुए हैं जिनका बहुत लाभ देश को आज मिल रहा है। जब ये Reforms किए जा रहे थे, तब भी इनका विरोध किया गया था, नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सारे Reforms समय की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं। 10 साल पहले भारत के बैंकिंग सेक्टर को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने बैंकिंग Reforms किए, IBC जैसे कानून बनाए। आज इन्हीं Reforms ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सेक्टर्स में से एक बना दिया है। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आज मजबूत और लाभदायक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लाभ 2023-24 में 1.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। हमारे बैंकों की मजबूती उन्हें ऋण आधार का विस्तार करने और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सक्षम बनाती है। सरकारी बैंकों का NPA भी लगातार कम हो रहा है। आज SBI रिकॉर्ड मुनाफे में है। आज LIC पहले से कहीं अधिक मजबूत है। आज HAL भी देश की डिफेंस इंडस्ट्री को ताकत दे रहा है। आज GST, भारत की इकॉनॉमी को formalise करने का, व्यापार-कारोबार को आसान बनाने का माध्यम बना है। अप्रैल महीने में पहली बार GST collection ने 2 लाख करोड़ रुपए का स्तर पार किया है। इससे राज्यों की आर्थिक ताकत भी बढ़ी है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट्स के प्रति भी आज पूरा विश्व आकर्षित हो रहा है।

माननीय सदस्यगण, एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्यबलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहें, इसके लिए सेनाओं में Reforms की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में अनेक Reforms किए हैं। CDS जैसे Reforms ने हमारी सेनाओं को नई मजबूती दी है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को

आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज के Reforms से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से इनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी हैं। ऐसे ही Reforms के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। फिलीपीन्स के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का रक्षा सौदा, defence export के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है। हम सभी के लिए ये खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70 प्रतिशत खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है। हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य साजो-सामान को विदेशों से नहीं मंगाना तय किया है। ये सभी हथियार और उपकरण अब सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है। तभी 4 दशक के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया। इसके तहत अब तक 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए सरकार ने कर्तव्यपथ के एक छोर पर नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना भी की है। ये प्रयास केवल वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र का नमन ही नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र प्रथम की अनवरत प्रेरणा का स्रोत भी हैं।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए ज़रूरी माहौल बनाने में जुटी है। बीते 10 वर्ष में ऐसे हर अवरोध को हटाया गया है जिसके कारण युवाओं को परेशानी थी। पहले अपने ही प्रमाण पत्र को अटेस्ट कराने के लिए युवाओं को भटकना पड़ता था। अब युवा सेल्फ अटेस्ट करके काम करते हैं। केंद्र सरकार की गुप-सी, गुप-डी भर्तियों से इंटरव्यू को खत्म किया गया है। पहले जो विद्यार्थी सिर्फ भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करते थे, उनके साथ अन्याय की स्थिति थी। मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर, इस अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। युवाओं को अब भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का

विकल्प भी मिला है। विगत 10 वर्षों में देश में 7 नए IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। मेरी सरकार इन संस्थानों को और मजबूत बनाकर आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या को भी बढ़ाएगी। सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। Atal Tinkering Labs, Start-up India और Stand-up India जैसे अभियान हमारे युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा Start-up ecosystem बन चुका है।

माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर-लीक की घटनाएं होती रही हैं। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की ज़रूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया, सभी में बड़े सुधार करने की दिशा में काम कर रही है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और बढ़ाने के लिए 'मेरा युवा भारत - MY Bharat' अभियान की शुरुआत भी की है। इसमें अब तक डेढ़ करोड़ से अधिक युवाओं का पंजीकरण हो चुका है। इस पहल से युवाओं में नेतृत्व कौशल और सेवा भावना का बीजारोपण होगा। आज हमारे युवाओं को खेलों में भी आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का परिणाम है कि भारत के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल्स जीत रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद पेरिस ओलंपिक भी शुरू होने जा रहा है। ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हर खिलाड़ी पर हमें गर्व है। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। इन

उपलब्धियों को और आगे ले जाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी भी कर रहा है।

माननीय सदस्यगण, जुलाई की पहली तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेजी राज में गुलामों को दंड देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही। इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी मेरी सरकार ने ही करके दिखाया है। अब दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता होगी, जो हमारे संविधान की भी भावना है। इन नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। आज जब देश, अलग-अलग क्षेत्रों में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पा रहा है तब ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। मेरी सरकार ने CAA कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को CAA के तहत नागरिकता मिली है मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भविष्य निर्माण के प्रयासों के साथ ही भारतीय संस्कृति के वैभव और विरासत को फिर से स्थापित कर रही है। हाल में नालंदा यूनिवर्सिटी के भव्य कैंपस के रूप में इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मात्र नहीं थी, बल्कि वो वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण थी। मुझे विश्वास है कि नई नालंदा यूनिवर्सिटी, भारत को ग्लोबल नॉलेज हब बनाने में सहायक सिद्ध होगी। मेरी सरकार का ये प्रयास है कि भावी पीढ़ियों को हज़ारों वर्षों की हमारी विरासत प्रेरणा देती रहे। इसलिए पूरे देश में तीर्थस्थलों को, आस्था और अध्यात्म के केंद्रों को सजाया-संवारा जा रहा है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार, विकास के साथ ही विरासत पर भी उतना ही गर्व करते हुए काम कर रही है। विरासत पर गर्व का ये संकल्प आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित वर्ग और सर्वसमाज के गौरव का प्रतीक बन रहा है। मेरी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। अब अगले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की

150वीं जयंती को पूरे देश में धूम धाम से मनाया जाएगा। देश, रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को भी व्यापक स्तर पर मना रहा है। पिछले महीने ही देश ने रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती का साल भर चलने वाला महोत्सव भी शुरू किया है। इससे पहले सरकार गुरु नानक देव जी का 550वां और गुरु गोबिन्द सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी धूमधाम से मना चुकी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से काशी तमिल संगमम्, सौराष्ट्र तमिल संगमम् जैसे उत्सवों की परिपाटी भी मेरी ही सरकार ने शुरू की है। इन आयोजनों से हमारी नई पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा मिलती है, और राष्ट्र पर गर्व का भाव और मजबूत होता है।

माननीय सदस्यगण, हमारी सफलताएं हमारी साझी धरोहर हैं। इसलिए, उन्हें अपनाने में संकोच नहीं स्वाभिमान होना चाहिए। आज अनेक सेक्टर्स में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये उपलब्धियां हमें हमारी प्रगति और सफलताओं पर गर्व करने के अपार अवसर देती हैं। जब भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो हमें गर्व होना चाहिए। जब भारत के वैज्ञानिक, चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतारते हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए। जब भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकॉनॉमी बनता है, तो हमें गर्व होना चाहिए। जब भारत, इतना बड़ा चुनाव अभियान, बिना बड़ी हिंसा और अराजकता के पूरा कराए, तो भी हमें गर्व होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमें Mother of Democracy के रूप में सम्मान देता है। भारत के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र के प्रति अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है, चुनाव से जुड़ी संस्थाओं पर पूरा भरोसा जताया है। स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें इस विश्वास को सहेज कर रखना है, इसकी रक्षा करनी है। हमें याद रखना होगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाना उसी डाल को काटने जैसा है जिस पर हम सब बैठे हैं। हमारे लोकतंत्र की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाने की हर कोशिश की सामूहिक आलोचना होनी चाहिए। हम सभी को वो दौर याद है जब बैलट पेपर छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए EVM को अपनाने का फैसला किया गया था। पिछले कई दशकों में EVM ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता की अदालत तक हर कसौटी को पार किया है।

माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी सदस्यों से अपनी कुछ और चिंताएं भी साझा करना चाहती हूं। मैं चाहूंगी कि आप सभी इन विषयों पर चिंतन-मनन करके इन विषयों पर ठोस और सकारात्मक परिणाम देश को दें। आज की संचार क्रांति के युग में विघटनकारी ताकतें, लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरारें डालने की साजिशें रच रही हैं। ये ताकतें देश के भीतर भी हैं और देश के बाहर से भी संचालित हो रही हैं। इनके द्वारा अफवाह फैलाने का, जनता को भ्रम में डालने का, misinformation का सहारा लिया जा रहा है। इस स्थिति को ऐसे ही बेरोक-टोक नहीं चलने दिया जा सकता। आज के समय में टेक्नॉलॉजी हर दिन और उन्नत हो रही है। ऐसे में मानवता के विरुद्ध इनका गलत उपयोग बहुत घातक है। भारत ने विश्व मंच पर भी इन चिंताओं को प्रकट किया है और एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की वकालत की है। हम सभी का दायित्व है कि इस प्रवृत्ति को रोकें, इस चुनौती से निपटने के लिए नए रास्ते खोजें।

माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में आज ग्लोबल ऑर्डर एक नई शकल ले रहा है। मेरी सरकार के प्रयासों से आज भारत, विश्व बंधु के रूप में दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। मानव-केंद्रित अप्रोच रखने की वजह से भारत आज किसी भी संकट के समय first responder और Global South की बुलंद आवाज बना है। कोरोना का महासंकट हो, भूकंप जैसी कोई त्रासदी हो या फिर युद्ध की स्थितियां, भारत मानवता को बचाने में आगे रहा है। भारत को देखने का विश्व का नज़रिया कैसे बदला है, ये इटली में हुई G-7 समिट में भी हम सभी ने अनुभव किया है। भारत ने अपनी G-20 अध्यक्षता के दौरान भी विश्व को अनेक मुद्दों पर एकजुट किया। भारत की अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को G-20 का स्थाई सदस्य बनाया गया है। इससे अफ्रीका महाद्वीप के साथ-साथ पूरे ग्लोबल साउथ का भरोसा मज़बूत हुआ है। Neighbourhood First Policy पर चलते हुए, भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को मज़बूत किया है। सात पड़ोसी देशों के नेताओं का 9 जून को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेना मेरी सरकार की इस प्राथमिकता को दर्शाता है। भारत, सबका साथ-सबका विकास की भावना के साथ, Indo-Pacific क्षेत्र के देशों के साथ भी सहयोग बढ़ा रहा है। पूर्वी एशिया हो या फिर मिडिल-ईस्ट और यूरोप, मेरी

सरकार कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रही है। भारत के विजन ने ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आकार देना शुरू किया है। ये कॉरिडोर, 21वीं सदी के सबसे बड़े गेमचेंजर्स में से एक सिद्ध होगा।

माननीय सदस्यगण, आने वाले कुछ महीनों में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। भारत का संविधान, बीते दशकों में हर चुनौती, हर कसौटी पर खरा उतरा है। जब संविधान बन रहा था, तब भी दुनिया में ऐसी ताकतें थीं, जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थीं। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए। आज 27 जून है। 25 जून, 1975 को लागू हुआ आपातकाल, संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तब पूरे देश में हाहाकार मच गया था। लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन-चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। अब भारत के उस भूभाग, हमारे जम्मू-कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां आर्टिकल 370 की वजह से स्थितियां कुछ और थीं।

माननीय सदस्यगण, राष्ट्र की उपलब्धियों का निर्धारण इस बात से होता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन कितनी निष्ठा से कर रहे हैं। 18वीं लोक सभा में कई नए सदस्य पहली बार संसदीय प्रणाली का हिस्सा बने हैं। पुराने सदस्य भी नए उत्साह के साथ आए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद क्या निर्णय लेती हैं, क्या नीतियां बनाती हैं, इस पर पूरे विश्व की नज़र है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ-साथ संसद के हर सदस्य का भी है। पिछले 10 वर्षों में जो Reforms हुए हैं, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, उससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि में

अवरोध पैदा न हो, ये हम सभी का दायित्व है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध, दो भिन्न बातें हैं। जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहां स्वस्थ चर्चा-परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल-पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगी।

माननीय सदस्यगण, हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने हमें “समानो मंत्रः समितिः समानी” की प्रेरणा दी है। अर्थात्, हम एक समान विचार और लक्ष्य लेकर एक साथ काम करें। यही इस संसद की मूल भावना है। इसलिए जब भारत तीसरे नंबर की इकॉनॉमी बनेगा तो देश की इस सफलता में आपकी भी सहभागिता होगी। हम जब 2047 में आज़ादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे, तो इस पीढ़ी को भी श्रेय मिलेगा। आज हमारे युवाओं में जो सामर्थ्य है, आज हमारे संकल्पों में जो निष्ठा है, हमारी जो असंभव सी लगने वाली उपलब्धियां हैं, ये इस बात का प्रमाण हैं कि आने वाला दौर भारत का दौर है। ये सदी भारत की सदी है, और इसका प्रभाव आने वाले एक हजार वर्षों तक रहेगा। आइए, हम सब मिलकर पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ, राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में जुट जाएं, विकसित भारत बनाएं।

आप सभी को बहुत शुभकामनाएं!

धन्यवाद,

जय हिन्द!

जय भारत!

Honourable Members, I extend my heartiest congratulations and best wishes to all the newly elected members of the 18th Lok Sabha. You all are here after winning the trust of voters of the country. Very few get this privilege to serve the nation and the people. I am confident that you will fulfil your responsibilities in the spirit of Nation First and will be a medium to fulfil the aspirations of 140 crore Indians. I wish Shri Om Birla Ji the very best for performing his exalted role as the Speaker of the Lok Sabha. He has vast experience in public life. I am confident that he will be successful in taking democratic traditions to new heights with his skills.

Honourable Members, I also express my gratitude to the Election Commission of India on behalf of crores of Indians today. This was the largest election in the world. About 64 crore voters performed their duty with enthusiasm and zeal. Women cast their votes in huge numbers this time also. A very heartening aspect of this election emerged from Jammu and Kashmir. The Kashmir Valley broke all records of voter turnout of many decades. In the last four decades, we had witnessed low voter turnout amidst shutdowns and strikes in Kashmir. Enemies of India continued to spread false propaganda at global forums, projecting it as an opinion of Jammu and Kashmir. But this time the Kashmir Valley has given a befitting reply to every such element within the country and outside. For the first time, the home voting facility was made available in this Lok Sabha Election. I convey my appreciation for the work done by all the personnel associated with the Lok Sabha elections and also extend my congratulations to them.

Honourable Members, the whole world is talking about the Lok Sabha Elections 2024. The world is witnessing that the people of India have elected a stable Government with clear majority, consecutively for the third term. This has happened after six decades. At a time when the aspirations of people of India are at their highest ever, people have reposed faith in my Government for the third consecutive term. The people of India have full faith that only my Government can fulfil their aspirations. Therefore, this election of 2024 has been an election of trust in policy, intention, dedication and decisions:

Trust in a strong and decisive Government

Trust in good governance, stability and continuity

Trust in honesty and hard work

Trust in security and prosperity

Trust in Government's guarantees and delivery

Trust in India's resolve to be Viksit Bharat

It is a stamp of approval for my Government's mission of service and good governance undertaken in the past 10 years. It is a mandate that the work of making India a developed nation continues uninterrupted and India attains its goals.

Honourable Members, the 18th Lok Sabha is historic in many ways. This Lok Sabha has been constituted in the early years of Amrit Kaal. This Lok Sabha will also be witness to the 75th year of adoption of the Constitution of India. I am confident that this Lok Sabha will script a new chapter on decisions for public welfare. My Government will present its first budget in the forthcoming session.

This budget will be an effective document of the Government's far-reaching policies and futuristic vision. Along with major economic and social decisions, many historic steps will also be seen in this budget. The pace of reforms will be further accelerated in tune with the aspirations of people of India for rapid development. My Government believes that there should be healthy competition among the states to attract investors from all over the world. This is the true spirit of competitive cooperative federalism. We will continue to move ahead with the belief that the development of the country lies in the development of the States.

Honourable Members, the resolve to Reform, Perform and Transform has made India the fastest growing economy in the world today. In 10 years, India has risen to become the 5th largest economy from being the 11th ranked economy. From 2021 to 2024, India has grown at an average rate of 8 percent annually. And this growth has not been achieved under usual circumstances. In recent years, we have seen the biggest pandemic in 100 years. India has achieved this growth amidst the global pandemic and despite ongoing conflicts in different parts of the world. This has been made possible due to reforms and major decisions undertaken in the national interest in the last 10 years. Today, India alone is contributing 15 percent of the global growth. Now, my Government is striving to make India the 3rd largest economy in the world. Achieving this goal will also strengthen the foundation of a developed India.

Honourable Members, my Government is giving equal importance to all the three pillars of the economy – Manufacturing, Services and Agriculture. PLI schemes and Ease of Doing Business have contributed to increasing investments

and employment opportunities on a large scale. Along with the traditional sectors, sunrise sectors are also being promoted in mission mode. Be it semiconductor or solar, Be it electric vehicles or electronic goods, Be it green hydrogen or batteries, Be it aircraft carriers or fighter Jets, India is expanding in all these sectors. My Government is also making continuous efforts to reduce the cost of logistics. The Government is also strengthening the services sector. Today, India is emerging as a leader in every sector from IT to Tourism and from Health to Wellness. And this is creating a large number of new opportunities for employment and self-employment.

Honourable Members, in the last 10 years, my Government has placed great emphasis on every aspect of rural economy. Agro-based industries, dairy and fishery-based industries are being expanded in villages. In this also, cooperatives have been accorded priority. The Government is creating a large network of Farmer Producer Organizations (FPOs) and cooperative organizations such as PACS. A major problem of small farmers is related to storage. Therefore, my Government has commenced work on a scheme to create the world's largest storage capacity in the cooperative sector. To enable farmers to meet their small expenses, more than Rupees 3,20,000 crore have been disbursed to them under PM-Kisan Samman Nidhi. In the initial days of its new term, my Government has transferred an amount of more than Rupees 20,000 crore to farmers. The Government has also effected a record increase in the MSP for Kharif crops.

Honourable Members, today's India is making changes in its agricultural system in line with its current requirements. Policies have been framed and

decisions taken guided by the thought that we become more self-reliant and increase farmers' income through increased exports. For example, the Government is providing all possible assistance to farmers to reduce dependence on other countries for pulses and oilseeds. New strategies are being formulated, keeping in mind the kind of food products that are in high demand in the global market. Nowadays, the demand for organic products is increasing rapidly in the world. Indian farmers have ample capacity to meet this demand. Therefore, the Government is strengthening natural farming and the supply chain of its related products. With these efforts, expenditure incurred by farmers on farming activities will reduce and their income will also increase further.

Honourable Members, today's India is known not for adding to the challenges the world is facing, but for providing solutions to the world. As a Vishwa-Bandhu, India has taken initiatives in providing solutions to many global problems. We are providing various solutions for issues ranging from climate change to food security and from nutrition to sustainable agriculture. We are also running a campaign to popularise our coarse grains – Shree Anna - as a super food, across the world. On India's initiative, the year 2023 was celebrated as International Year of Millets across the world. You have also seen that International Yoga Day was recently celebrated as a global event. The prestige of this great legacy of India is continuously rising in the world. By promoting Yoga and Ayush, India is helping create a healthy world. My Government has also increased renewable energy capacities manifold. We are achieving our climate related targets much ahead of schedule. Our initiatives towards Net Zero are an

inspiration for many countries. A record number of countries have associated with us on our initiatives such as International Solar Alliance.

Honourable Members, the future is going to be Harit Yug or Green Era. My Government is taking all necessary steps in this direction. We are increasing investments in Green Industries, leading to increase in Green Jobs. Be it Green Energy or Green Mobility, we are working with ambitious goals on all fronts. My Government is also committed to making our cities the best living spaces in the world. Living in cities which are pollution free, clean and with amenities is the right of Indian citizens. Investments on an unprecedented scale have been made, particularly in small cities and towns, in last 10 years. India is the world's third largest domestic aviation market. In April 2014, India had only 209 airline routes. This number has increased to 605 by April 2024. This increase in the aviation routes has directly benefitted Tier-2 and Tier-3 cities. In 10 years, Metro has reached 21 cities. Work is going on in many schemes such as Vande Metro. My Government is working to make India's public transport system one of the best in the world.

Honourable Members, my Government is working on those modern parameters which will enable India to stand on an equal footing with developed countries. In this direction, Infrastructure development has emerged as the new face of a changing India. My Government has, in 10 years, constructed more than 3,80,000 kilometres of village roads under the PM Gram Sadak Yojana. Today, we have an expanding network of National Highways and Expressways in the country. The pace of construction of National Highways has more than doubled.

Work on the High-Speed Rail Ecosystem between Ahmedabad and Mumbai is also progressing at a rapid pace. My Government has decided to conduct feasibility studies for bullet train corridors in the North, South and East of the country. For the very first time, work on inland waterways has started on such a large scale. The North-East will benefit immensely from this initiative. My Government has increased the allocation for the development of the North-Eastern Region by more than four times, in the last 10 years. The Government is working to make this region a strategic gateway under its Act East Policy. Connectivity of all kinds is being expanded in the North-East. Development works are being taken up in every field including education, health, tourism and employment. A semi-conductor plant is being established in Assam at a cost of Rupees 27,000 crore. The North-East will also be a hub of Made in India chips. My Government is continuously working for lasting peace in the NorthEast. In the last ten years, many old disputes have been resolved, many important agreements have been reached. The work of withdrawing AFSPA from the disturbed areas of the NorthEast is also underway in a phased manner by accelerating development in those areas. These new initiatives in every aspect of development in the country are heralding the future of India.

Honourable Members, my Government which is committed to women-led development has started a new era of women empowerment. Women in our country had been demanding greater representation in Lok Sabha and Vidhan Sabha for a long time. Today, they stand empowered by the enactment of Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Over the past decade, various Government schemes

have led to greater economic empowerment of women. As you are aware, during the last 10 years, majority of the 4 crore PM Awas houses have been allotted to women beneficiaries. Now, at the very start of the third term of my Government, approval for construction of 3 crore new houses has been accorded. Most of these houses will be allotted to women beneficiaries. Over the last 10 years, 10 crore women have been mobilised into Self Help Groups. My Government has started a comprehensive campaign to make 3 crore women Lakhpati Didis. For this, financial support to the Self Help Groups is also being increased. The endeavour of the Government is to improve skills and sources of income, and enhance respect for women. The NAMO Drone Didi Scheme is contributing towards achieving this goal. Under this Scheme, women belonging to thousands of Self Help Groups are being provided with drones and also being trained as Drone Pilots. My Government has also recently started Krishi Sakhi Initiative. Under this initiative, till date, 30 thousand women belonging to Self Help Groups have been provided with Krishi Sakhi Certificates. Krishi Sakhis are being trained in modern agricultural practices so that they can help farmers in further modernization of Agriculture.

Honourable Members, the effort of my Government is also to maximise the savings of women. We are well aware of the popularity of Sukanya Samriddhi Yojana under which a higher interest rate is being provided to girls on their bank deposits. Women are also immensely benefitting from the schemes providing free ration and affordable gas cylinders. Now my Government has also brought a scheme to bring down the electricity bill to zero and generate income by selling

electricity. Solar panels are being installed on the rooftops of houses under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. For this, my Government has been providing a support of upto Rupees 78,000 per family. More than 1 crore families have already been registered under this scheme within a very short time. The electricity bill of houses with rooftop solar installation has come down to zero.

Honourable Members, achieving the goal of Viksit Bharat will be possible only when the poor, youth, women and farmers of this country are empowered. Therefore, top most priority is being accorded to these four pillars in the schemes of my Government. Our effort is to ensure that the benefit of every Government Scheme reaches them. This is the saturation approach. When the Government works with the intention that not a single person is left out of the Government schemes, it benefits everyone. It is because of the implementation of Government Schemes with the saturation approach over the last 10 years that 25 crore Indians have been brought out of poverty. This includes families of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and all other social and regional groups. In the last 10 years, focus on last mile delivery has changed the lives of these sections. The change is more evident especially in the tribal communities. A scheme like PM JANMAN with an allocation of more than Rupees 24,000 crore is proving to be a means of development of the most backward tribal communities. The Government is also providing soft loans to the disadvantaged groups through PM-SURAJ portal for making livelihood opportunities available. My Government is developing affordable indigenous assistive devices for Divyang brothers and

sisters. PM Divyasha Kendras are also being expanded to all parts of the country. This commitment to serve the deprived is true Social Justice.

Honourable Members, as a mark of respect for the country's labour force, the welfare and empowerment of workers are my Government's priority. My Government is integrating all the Social Security Schemes for workers. The coverage of accident and life insurance is being expanded by leveraging the networks of Digital India and the Post Offices. The scope of PM SVANidhi will be expanded and street vendors in rural and semi-urban areas will also be brought under its ambit.

Honourable Members, Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar believed that the progress of any society depends on the progress of the lower strata of the society. Empowerment of the poor has been the foundation of the achievements and progress of the nation in the last 10 years. For the first time my Government has made the poor realise that the Government is at their service. In the difficult times of the Corona pandemic, the Government started PM Garib Kalyan Anna Yojana to provide free ration to 80 crore persons. The benefit of this scheme is also being given to those families who have come out of poverty, so that they do not slip back into poverty. Swachh Bharat Mission has also made the dignity of the poor and their health a matter of national significance. For the first time, toilets were built for crores of poor people in the country. These efforts give us the confidence that today the nation is following the ideals of Mahatma Gandhi in the true spirit. My Government is providing free health services to 55 crore beneficiaries under Ayushman Bharat Yojana. The opening of 25,000 Jan

Aushadhi Kendras in the country is also progressing at a fast pace. Further, the Government is going to take yet another decision in this area. Now all the elderly above 70 years of age will also be covered and get benefit of free treatment under Ayushman Bharat Yojana.

Honourable Members, often, due to adversarial mindset and narrow selfishness, the basic spirit of democracy has been greatly undermined. It affects the parliamentary system as well as the developmental journey of the nation. During the phase of unstable governments in the country that lasted several decades, many governments, even if willing, were neither able to bring reforms nor take critical decisions. The people of India have now changed this situation by their decisive mandate. Many such reforms have taken place in the last 10 years which are greatly benefitting the nation today. Even when these reforms were being taken up, they were opposed and attempts were made to spread negativity. But all these reforms have stood the test of time. Ten years ago, to save India's banking sector from collapsing, the Government brought banking reforms and made laws like IBC. Today, these reforms have made India's banking sector one of the strongest banking sectors in the world. Our public sector banks are robust and profitable today. Profits of public sector banks have crossed Rupees 1.4 lakh crore in 2023-24 which is 35% higher than last year. The strength of our banks enables them to expand their credit base and contribute to the economic development of the nation. The NPAs of Public Sector banks are also continuously decreasing. Today SBI is earning record profits. Today LIC is stronger than ever. Today HAL is also giving strength to the country's defence

industry. Today, GST has become a medium to formalise India's economy and is helping make business and trade easier than before. For the first time, in the month of April, GST collection has crossed Rupees 2 lakh crore. This has also strengthened the states economically. Today, the entire world is excited about Digital India and Digital Payments.

Honourable Members, modernisation of our armed forces is essential for a strong India. Reforms in our armed forces should be a continuous process so that our forces maintain their supremacy during wars. Guided by this, my Government has introduced many reforms in the defence sector in the last 10 years. Reforms like CDS have given new strength to our defence forces. My Government has taken many important steps to make the defence sector self-reliant. The defence sector has greatly benefitted from the reforms in ordnance factories. More than 40 Ordnance factories have been restructured into 7 Defence Sector Enterprises, resulting in improvement of their capacity and efficiency. It is due to such reforms that India is now manufacturing defence equipment worth more than Rupees 1 lakh crore. In the last decade, our defence exports have increased more than 18 times to the level of Rupees 21,000 crore. The BrahMos Missile defence deal with the Philippines has strengthened India's standing in defence export sector. By providing encouragement to youth and their startups, the Government has been able to lay down a strong foundation for a self-reliant defence sector. My Government is also developing two defence corridors, in Uttar Pradesh and Tamil Nadu. It is a matter of joy for all of us that last year nearly 70 per cent of the total procurement of the defence forces has been sourced from Indian manufacturers

only. Our defence forces have decided not to import over 500 defence items. All these arms and defence related equipments are being procured only from Indian companies. My Government has always given priority to the needs of the personnel in the armed forces. That is why after 4 decades One Rank One Pension has been implemented. Under this, Rupees 1,20,000 crore have been disbursed till date. In the honour of our martyrs, the Government has also established the National War Memorial at one end of Kartavya Path. These efforts are not only salutations from a grateful nation for its brave soldiers but also a source of constant inspiration of the ideal of Nation First.

Honourable Members, my Government is involved in creating an enabling environment for the youth of this country to dream big and realise those dreams. In the last 10 years, every such obstacle which caused trouble to our youth has been removed. In the past the youth had to run from pillar to post in order to get their certificates attested. Now their self-attestation is sufficient. Interviews for recruitment into Group-C and Group-D posts of the Central Government have been abolished. Earlier, the students who studied in Indian languages faced an unfair situation. With the implementation of the new National Education Policy, my Government has been able to remove this injustice. Now students can take up engineering courses in Indian languages. In the past 10 years 7 new IITs, 16 IIITs, 7 IIMs, 15 new AIIMS, 315 medical colleges and 390 universities have been established. It is the endeavour of the Government to further strengthen these institutions and increase their numbers as per requirement. The Government is working towards establishing a Digital University as well. Programmes like Atal

Tinkering Labs, Start-up India and Stand-up India, have helped improve the capacity of youth of the country. It is due to these efforts that today India has become the third largest Start-up eco-system in the world.

Honourable Members, it is the continuous endeavour of the Government to provide right opportunities to the youth of the country to demonstrate their talent. Whether it is competitive examinations or Government recruitment there should be no reason for any hindrance. This process requires complete transparency and probity. Regarding the recent instances of paper leak in some examinations, my Government is committed to a fair investigation and ensuring strict punishment to the culprits. Even earlier, we have witnessed many instances of paper leaks in different States. It is important that we rise above party-politics and undertake concrete measures nationwide. Parliament has also enacted a strict law against unfair means in examinations. My Government is working towards major reforms in examination related bodies, their functioning and all aspects of the examination process.

Honourable Members, for further increasing the participation of youth in nation building, my Government has launched 'Mera Yuva Bharat (MY Bharat)' campaign. So far, more than 1.5 crore youth have registered for it. This initiative will inculcate leadership skills and seed the spirit of service among the youth. Today our youth is getting new opportunities to move forward in sports as well. Due to effective efforts of my Government, young Indian players are winning a record number of medals at global platforms. The Paris Olympics is also going to start in a few days. We are proud of every athlete representing India at the

Olympics. I convey my best wishes to them. To take these achievements further, the Indian Olympic Association is also preparing to host the 2036 Olympic Games.

Honourable Members, the Bharatiya Nyay Sanhita will come into force in the country from the first of July. During the British regime, there was the mindset to punish the subjects. Unfortunately, the same penal system of the colonial era continued for many decades after Independence. The idea of changing this was much talked about for many decades, but it is my Government which has shown the courage to do it. Now justice will get priority over punishment, which also conforms to the spirit of our Constitution. These new laws will speed up the judicial process. Today, when the country is becoming free of the colonial mindset in different aspects, this is a big step in that direction. It is also a real tribute to our freedom fighters. My Government has started granting citizenship to refugees under the CAA. It has ensured a dignified life to many families who have suffered due to Partition. I wish a better future for the families who have been granted citizenship under CAA.

Honourable Members, while building the future, my Government is re-establishing the splendour and heritage of Indian culture. Recently, a new chapter has been added to it, in the form of the grand campus of Nalanda University. Nalanda was not just a university, but a testimony to India's glorious past as a global knowledge hub. I am confident that the new Nalanda University will help in making India a Global Knowledge Hub. It is the endeavour of my Government to continue to inspire the future generations with our legacy of thousands of years.

That is why places of pilgrimage and centres of faith and spirituality are being spruced up across the country.

Honourable Members, my Government is working with the same pride for heritage as it has been working for development. This resolve for pride in heritage is becoming a symbol of honour for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the deprived and all communities. My Government started celebrating the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda as Jan Jatiya Gaurav Divas. The 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda will be celebrated across the country next year with great enthusiasm. The country is also celebrating the 500th birth anniversary of Rani Durgavati on a large scale. Last month, the country has started the year-long celebration to mark the 300th birth anniversary of Rani Ahilyabai Holkar. Earlier, the Government also celebrated the 550th Prakash Parv of Guru Nanak Dev Ji and the 350th Prakash Parv of Guru Gobind Singh Ji with great fervour. The tradition of celebrating festivals like Kashi Tamil Sangamam and Saurashtra Tamil Sangamam in the spirit of 'Ek Bharat Shreshtha Bharat' was also initiated by my Government. The new generations get inspiration for nation building from these events, and the sense of national pride is made stronger.

Honourable Members, our successes are our shared heritage. We should, therefore, take pride and not hesitate in embracing them. Today, India is performing well in various sectors. These achievements give us immense opportunities to make us feel proud of our progress and successes. We should feel proud when India performs well in digital payments globally. We should feel

proud when our scientists successfully land Chandrayaan on the South Pole of the Moon. We should feel proud when India becomes the fastest growing economy in the world. We should also feel proud when India conducts such a large election exercise without any major violence and disorder. Today, the whole world respects us as the Mother of Democracy. The people of India have always demonstrated complete trust in democracy and expressed full faith in the electoral institutions. We need to preserve and protect this trust to sustain our robust democracy. We must realise that hurting the faith of people in democratic institutions and the electoral process is like cutting the very branch on which we all are sitting. We should collectively denounce every attempt to undermine the credibility of our democracy. We all remember those times when ballot papers were snatched and looted. To ensure the sanctity of the electoral process, it was decided to use EVMs. The EVM has passed every test, from the Supreme Court to the people's court, in the last few decades.

Honourable Members, I also want to share with you some of my concerns. I would urge you to introspect on these issues and give concrete and constructive solutions to the country. In this era of communication revolution, disruptive forces are conspiring to weaken democracy and create fissures in the society. These forces are present within the country and are also operating from outside the country. These forces resort to rumour mongering, misleading the people and misinformation. This situation cannot be allowed to continue unchecked. Today, technology is advancing every day. In such a situation, its misuse against humanity can be extremely harmful. India has expressed these concerns at the

international forums also and advocated for a global framework. It is our responsibility to stop this tendency and find new ways and means to address this challenge.

Honourable Members, the global order is taking a new shape in this third decade of 21st century. Due to the efforts of my Government, Bharat is giving a new confidence to the world as a Vishwa-Bandhu. Due to its human-centric approach, India today is the first responder in any crisis and has become a strong voice of the Global South. India has been at the forefront in safeguarding humanity; be it the Corona crisis or an earthquake or a war. The way the world now views India was evident during the G-7 summit held in Italy. India also brought the world together on various issues during her G-20 presidency. It was during India's presidency that the African Union was made a permanent member of the G-20. This has strengthened the confidence of Africa and the entire Global South. Following the Neighbourhood First Policy, India has strengthened its relations with neighbouring countries. Participation of the leaders of seven neighbouring countries in the swearing-in ceremony of the Union Council of Ministers on June 9 reflects this priority of my Government. India, in the spirit of Sabka Saath-Sabka Vikas, is also increasing cooperation with the countries of the Indo-Pacific region. Be it East Asia or Middle-East and Europe, my Government is giving great emphasis on connectivity. It is India's vision that has given shape to the India Middle East Europe Economic Corridor. This corridor will prove to be one of the biggest gamechangers of 21st century.

Honourable Members, in a few months, India is going to complete 75 years as a Republic. The Constitution of India has stood up to every challenge and every test in the past decades. Even when the Constitution was in the making, there were forces in the world who wished India to fail. Even after the Constitution came into force, it was attacked many times. Today is 27th June. The imposition of Emergency on 25th June, 1975, was the biggest and darkest chapter of direct attack on the Constitution. The entire country felt outraged. But the country emerged victorious over such unconstitutional forces as the traditions of the republic lie at the core of India. My Government also does not consider the Constitution of India as just a medium of governance; rather we are making efforts to ensure that our Constitution becomes a part of public consciousness. With this very objective in mind, my Government has started celebrating 26th November as Constitution Day. Now the Constitution has also fully come into force in that part of India, our Jammu and Kashmir, where the conditions were different due to Article 370.

Honourable Members, achievements of the nation are determined by our sincerity in discharging our responsibilities. In the 18th Lok Sabha, many new members have become part of the parliamentary system for the first time. Old members have also returned with new enthusiasm. You all know that the present times are very favourable for India in every way. In the coming years the decisions taken and policies framed by the Government and the Parliament of India will be keenly watched by the whole world. It is the responsibility of every Member of Parliament as well as of the Government, to ensure the country gets

utmost benefits during this favourable period. With the reforms that have taken place in the last 10 years and the new confidence that has been infused in the country, we have gained a new momentum to make India a developed nation. We all need to always remember that making India a developed nation is the aspiration and resolve of every citizen of the country. All of us are responsible for ensuring that no obstacles come in the way of achieving this resolution. Opposition of policies and obstruction of parliamentary functioning are two different things. When Parliament conducts its business smoothly, when healthy deliberations take place here, when far-reaching decisions are taken, then the people repose confidence not only in the Government but also in the entire system. Therefore, I am confident that every moment of Parliament will be fully utilised and public interest will be given priority.

Honourable Members, in our Vedas, our sages have inspired us with the message “**Samano Mantrah Samitih Samani**”. That is, we work together with a common idea and goal. This is the very spirit of this Parliament. Therefore, when India becomes the third largest economy, you will also be partners in this achievement. When we celebrate the hundredth anniversary of Independence in 2047 as a developed India, this generation will also get credit. The potential that our youth have today, The dedication we have in our resolutions today, Our seemingly impossible achievements, All these testify that the era to come is the era of India. This century is India's century, and its impact will last for a thousand years to come. Let us all together, with full devotion to our duties, get actively involved in fulfilling national resolutions and make India a developed nation.

Best wishes to all of you!

Thank You,

Jai Hind!

Jai Bharat!

12.42 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Notices of Amendments to Motion of Thanks on President's Address

माननीय अध्यक्ष: जैसा कि माननीय सदस्यों को लोक सभा के दिनांक 26 जून, 2024 के समाचार भाग – 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की सूचनाएं आज शाम पांच बजे तक दी जा सकती हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 3, महासचिव ।

12.44 hrs

ASSENT TO BILLS

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table the following eight Bills passed by the Houses of Parliament during the Fifteenth Session of Seventeenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 2nd February, 2024:-

- I The Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024
- II The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024
- III The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024
- IV The Finance Bill, 2024
- V The Appropriation (Vote on Account) Bill, 2024
- VI The Appropriation Bill, 2024
- VII The Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2024
- VIII The Jammu and Kashmir Appropriation (No.2) Bill, 2024

I also lay on the Table copies, duly authenticated by the Secretary-General, Rajya Sabha of the following four Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:-

- I The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024
- II The Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024
- III The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2024

IV The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order
(Amendment) Bill, 2024

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राज्य सभा में मंत्रिमंडल का परिचय होना है, इसलिए वहां गए हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 28 जून, 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.45 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Friday, June 28, 2024/Ashadha 7, 1946 (Saka).*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following address:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Seventeenth Edition)
